(ग) इस संबंध में रूस की प्रतिक्रिया क्या है ?

विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, इलेक्ट्रानिकी विभाग, तथा महासागर विकास विभाग में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री रंग राजन कुमारमंगलम) : (क) भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के उपग्रह के साथ-साथ प्रमोचक राकेट कार्यक्रम भी हैं । प्रमोचक राकेट कार्यक्रमों की सूची में, उपग्रह प्रमोचक राकेट (एस०एल०वी०) संवर्धित उपग्रह प्रमोचक राकेट (ए०एस०एल० वी.) ध्रुवीय उपग्रह प्रमोचक राकेट (पी०एस०एल०वी०) और भूस्थाकाली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०के०एल०एस०वी) को सम्मिलित किया जा सकता है । उपग्रह कार्यक्रम के अंतर्गत, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह (इन्सैट नामक संचार उपग्रह आई०आर०एस० नामक सुदूर संवेदन उपग्रह तथा निम्न भू-कक्षीय उपग्रह जैसे विस्तृत रोहिणी उपग्रह-खंड) को उल्लेख किया जा सकता ऐसी संभावना है कि अमेरिका का निर्णय कुछहद तक या दूसरी दृष्टि से इन सभी कार्यक्रमों को प्रभावित करेगा । लेकिन, इन आकस्मिकताओं के विरुद्ध इसरो द्वारा स्वयं को तैयार करने की कार्यवाहियों को देखते हुए ऐसी आशा की जाती है कि वर्षों के लिए लगाया गया प्रतिबंध राकेट कार्यक्रमों को ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाएगा । फिर भी उपग्रह कार्यक्रमों पर इसका प्रभाव पड़ सकता है । इसरो के लिए यह संभव है कि वह आठवीं योजना में स्वीकृत अंतरित कार्यक्रमों को उपयुक्त परिवर्तनों के साथ जारी रखे ।

(ख) सरकार ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के विरुद्ध लगाए गए प्रतिबंध के बारे में अमरीकी निर्णय के लिए खेद प्रकट किया है । हमारे अंतरिक्ष कार्यक्रम की शांतिपूर्ण प्रकृति सर्वविदित है । हमने इस बात की पुनरावृत्ति की है कि इसरो द्वारा प्राप्त किए जा रहे क्रायोजैनिक इंजिन और इससे संबद्ध प्रौद्योगिकी का कोई सैन्य उपयोग नहीं है तथा इनका उपयोग केवल मौसम की भविष्यवाणी, दूरसंचार और संसाधनों के सर्वेक्षण से संबंधित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, अपने उपग्रह को कक्षा में स्थापित करने वा० भूतुल्यक ली उपग्रह प्रमोचक राकेट (जी०एस०एल०वी०) के विकास कार्यक्रम के लिए किया जाएगा ।

अमरीका विचार है कि इसरो और ग्लोवकास्मास के विरुद्ध लगाया गया प्रतिबंध उसके ऐसे कानून के तहत अनिवार्य है जो अंतरिक्ष प्रमोचक राकेट और मिसाइल प्रौद्योगिकी के बीच कोई भेद नहीं रखता है यदि वे मिसाइल टैक्नोलाजी कंट्रोल रिजाइन (एम०टी०सी०आर) के अंतर्गत निर्दिष्ट पैरामीटरों का अतिक्रमण करते हैं ।

(ग) इसरो और ग्लैवकास्मास के बीच हुआ ठेका प्रभावी है और क्रियान्वित किया जा रहा है । भारत ठेके में निर्दिष्ट दायित्वों का पालन करेगा तथा हम आशा करते हैं कि रूस भी बदले में इसका पालन करेगा और अपने दायित्वों का निर्वहन करेगा ।

U.S. Sanctions on GSLV programme

1635. SHRI KRISHNA KUMAR BIRLA: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) what is the ultimate impact of U.S. sanctions on country's GSLV programme slated to be launched in 1995 and on the ongoing space projects; and

(b) whether the Government of India have protested against U.S. sanctions, if so, the outcome thereof?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY, DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) The cryogenic agreement with Russians is proceeding as per schedule for the planned GSLV launch by 1995-96. The Government is reviewing all the implications of the recent

ban on the approved Space Programme during the Eighth Plan period and feels confident that with suitable adjustments, the programmes could go on. Long term measures as appropriate with necessary outlays to ensure timely action for self-reliance are also underway.

(b) Government regret the US decision to impose sanctions against ISRO. The peaceful nature of our space programme is well known. We have reiterated that the cryogenic engines and related technology being sought by ISRO has no military applictations and will only be used in the Geo-synchronous Satellite Launch Vehicle (GSLV) development programme for putting our satellite in orbit for the purposes of weather forecasting, telecommunications and resource survey. The US maintains that sanctions against ISRO and GLAVKOSMOS were mandated by its legislation which does not make any distinction between technology for space launch vehicles and missiles as long it exceeds the parameters specified under the Missile Technology Control Regime (MTCR).

Indian Space Research Organisation contribution to defence potential

1636. CHOWDHRY HARI SINGH: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the United States are worried about Indian Space Research Organisation's possible contribution to defence potential of India; and

(b) if so, what is the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY DEPARTMENT OF ELECTRONICS AND DEPARTMENT OF OCEAN DEVELOPMENT AND THE MINISETR OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI P. R. KUMARAMANGALAM): (a) The space programmes of ISRO are for peaceful purposes only.

(b) Does not arise.

SHRI DIPEN GHOSH: Madam, where is the Prime Minister? Where is the Home Minister? (*Interruptions*)

SHRI S. JAIPAL REDDY (Andhra Pradesh): Where is the Prime Minister? We want that the Prime Minister should come before the House. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Papers to be laid on the Table? (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH (West Bengal): We want the Prime Minister. Please call the Prime Minister. (*Interruptions*)

THE DEPUTY CHAIRMAN: Let the Papers be laid first. (*Interruptions*)

SHRI DIPEN GHOSH: What papers are they going to lay on the Table? (*Interruptions*)

PAPERS LAID ON THE TABLE

Notifications of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department)

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI M. M. JACOB): Madam, I, on behalf of Shri G. Venkat Swamy lay on the Table, under sub-section (3) of section 3 of the Punjab State Legislature (Delegation of Powers) Act, 1987, a copy each (in English and Hindi) of the following Notifications of the Ministry of Law, Justice and Company Affairs (Legislative Department):—

(1) Notification dated 11th July, 1991, publishing the Punjab Panchayat Samitis and Zila Parishads (Temporary Super-session) Second Amendment Act, 1991.

[Placed in Library. *See* No. LT-2343/92].